

## ‘किसान सिर्फ खेती नहीं करते, वे जीवन की नींव रखते हैं’

मु.मंत्री भजनलाल ने बीकानेर में आयोजित किसान सम्मेलन को किसानों के सम्मान को समर्पित बताया

मुख्यमंत्री ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर जोर दिया और इसके लिए तीस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

किसान सम्मेलन एवं एफ.पी.ओ. कार्यक्रम में तीस हजार किसानों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान हस्तांतरित किया गया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 30 हजार किसानों को 137 करोड़ रुपये का अनुदान, हस्तांतरण किया।

चुड़ें, जिससे वे लाभ की खेती कर खुद को सशक्त बना सकें। शर्मा बुधवार को बीकानेर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत आयोजित किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने कहा, किसान सिर्फ

खेती नहीं करते, वे जीवन की नींव रखते हैं। आज बीकानेर में हुए किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम में 30 हजार किसानों को 137 करोड़ रुपये का अनुदान, हस्तांतरण किया गया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती किये जाने पर 30 हजार रु. की प्रोत्साहन राशि के दिशा-निर्देश जारी किए गए। पीएमएफएमई योजना के

तीन एफपीओ को अनुदान के तथा एक एफपीओ को शेयर मनी के बैंक वितरण किए गए। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 10 हजार एफ.पी.ओ. का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में 72 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का हस्तांतरण, लगभग 47

लाख किसानों को 29 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। शर्मा ने कहा कि उन्होंने खेती का हर काम किया है तथा वे किसानों की समस्या को भलीभांति समझते हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘गहलोत सिर्फ टिक्टर पर ही एक्टिव रहते हैं’

बीकानेर, 26 मार्च (कास)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टिक्टर पर सक्रियता व पूर्व वादों को लेकर गहलोत पर जमकर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री टिक्टर पर सक्रिय रहते हैं लेकिन विधानसभा में एक दिन भी नहीं आये। वे दिनभर टिक्टर पर चलते हैं और सुबिखों में रहना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री बीकानेर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा- सिर्फ सोशल मीडिया

मुख्यमंत्री भजनलाल ने किसान सम्मेलन में कहा, गहलोत एक बर्ही विधानसभा में नहीं आए।

पर सक्रिय रहने से जनता के दुख-दर्द कम नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत टिक्टर पर रहने से पहले अपने पांच साल की सरकार के कामों को देख लें।

इस पर गहलोत ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि आज मुख्यमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में जनता की शिकायत बताने वाले और सरकार की कमियां उजागर करने वाले मेरे टिक्टर पर टिप्पणी की है।

मुख्यमंत्री जी, मैं आपको लगभग ढाई साल पुराना आपका टिक्टर याद दिलाता चाहता हूँ, जिसमें आपने कांग्रेस सरकार से बाजरे की एमएएसपी पर खरीद की मांग की थी और विरोध जताया था।

अमेरिका से आयातित सामान पर भारत, टैरिफ आधा करने को तैयार

इस टैरिफ में कमी से 23 अरब डॉलर का नुकसान होगा भारत को, पर, भारत से अमेरिका को निर्यात, जिसकी कीमत 66 अरब डॉलर आंकी जाती है, सुरक्षित रहने की आशा है

-सुकुमार साह-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 26 मार्च। अमेरिका के रिसिप्रोकल टैरिफ (जो जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएगा) जो 2 अप्रैल 2025

66 अरब डॉलर के निर्यात को रिसिप्रोकल टैरिफ की मार से बचना है। लेकिन प्रस्तावित कटौती इस बात पर निर्भर है कि अमेरिका अपने सुनियोजित करों से कितनी राहत देता है। प्रमुख उद्योगों जैसे फार्मास्युटिकल्स और

सबसे पहले भारत, इलैक्ट्रिक वाहनों की बैट्री के निर्माण में आवश्यक सामान पर टैरिफ बहुत कम करना चाहता है, जिससे स्थानीय उद्योगपतियों व निर्माताओं का माल विदेशों में मार्केट किया जा सके।

सरकार द्वारा किये गये आंकलन के अनुसार, भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट का 87 प्रतिशत हिस्सा, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित टैरिफ से प्रभावित होगा। अतः भारत सरकार अमेरिका से आयातित माल पर टैरिफ में 5 से 30 प्रतिशत की कमी कर सकती है।

से लागू होने जा रहा है, के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार आधे से ज्यादा अमेरिकन आयात पर टैरिफ घटाने का विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य अमेरिका को हो रहे भारत के

आंटो मोबाइल्स को इस समय काफी खतरा है, हालांकि कुछ कृषि उत्पादों की कटौती से राहत दी जा सकती है। यह कदम अगले सप्ताह से लागू (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुँची पुलिस

स्टोर रूम व आसपास की जगह सील कर दी गई है

नई दिल्ली, 26 मार्च। दिल्ली पुलिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुँचकर उनके स्टोर रूम और आसपास की जगह सील कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार महला अपनी टीम के साथ घटना वाली जगह पर पहुँचे। आग लगने वाली जगह को जांच कमेटी के कहने पर सील किया है। दिल्ली पुलिस ने स्टोर रूम और आसपास की जगह का दौरा किया।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी घर से कथित तौर पर आधी जली हुई नकदी मिलने के मामले में लगी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस संजिव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि यह व्यापक जनहित

सुप्रीम कोर्ट की जाँच कमेटी के आग्रह पर दिल्ली पुलिस ने यह कार्यवाही की है।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया।

से संबंधित है। इस पर सीजेआई ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होगी। वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सराहनीय काम किया है, लेकिन एफआईआर की जरूरत है। इस पर सीजेआई ने कहा, सर्वजनिक बयान न दें।

मामले में एक महिला और सह-याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर ऐसा मामला किसी आम नागरिक के खिलाफ

होता तो सीबीआई और डीडी जैसी कई जांच एजेंसियां उसके पीछे लग जातीं। सीजेआई ने कहा, यह काफी है। याचिका पर उसी के अनुसार सुनवाई होगी। नेदुम्परा और तीन अन्य लोगों ने रविवार को एक याचिका दायर कर पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।

कथित नकदी की बरामदगी 14 मार्च को रात करीब 11.35 बजे जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगने के बाद हुई। मौके पर अग्निशमन अधिकारी पहुँचे थे। विवाद के मद्देनजर, सर्वोच्च न्यायालय के कोलॉजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को उनके पैतृक इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेजने की सिफारिश की। 22 मार्च को सीजेआई ने आरोपों की आंतरिक जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया और घटना में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की जांच रिपोर्ट अपलोड करने का फैसला किया।

पेपर लीक केस, तृतीय श्रेणी अध्यापक राजेन्द्र यादव सस्पेंड

जयपुर, 26 मार्च। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर लीक करने के मामले में तृतीय श्रेणी अध्यापक को शिक्षा विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आरोपी जेब शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमाल राजकीय उच्च माध्यमिक खतीपुरा में तैनात था, तब उसने पेपर आउट किया था। आरोपी जगदीश

आरोपी जगदीश विश्वादी गैंग का सदस्य था तथा कई परीक्षाओं के पेपर लीक में लिप्त था।

विश्वनाई गैंग का सक्रिय सदस्य है। एसओजी ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की थी और अभी वह न्यायिक अभिरक्षा में है। राजेन्द्र कुमार यादव मेजर दिग्विजय सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खतीपुरा, जयपुर में अध्यापक के पद पर कार्यरत था। पंकज चौधरी उर्फ यूनिवर्सिटी जयपुर जगदीश विश्वादी के साथ संगठित गिरोह में शामिल होकर राजेन्द्र यादव प्रतियोगी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

न्यायालय कुछ भी कहते रहें, ‘बुलडोजर न्याय’ का चलन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा

राजनीतिक नेतृत्व को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं लगती कि सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर जस्टिस के बारे में क्या गाइडलाइन्स हैं

-श्रीनन्द झा-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 26 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने चार महीने पहले ‘न्याय से परे के ध्वस्तीकरण (एक्स्ट्रा-जुडिशियल डिमांड्स) को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, तथा म्यूनिसिपल अधिकारियों के लिये गाइडलाइन जारी कर दी थीं, जिन्हें भवन गिराने की कार्यवाही करने से पहले ध्यान में रखना अनिवार्य था, इसके बावजूद, ‘बुलडोजर जस्टिस’ यथावत एवं अक्षुण्ण रूप से जारी है। पिछले सोमवार को, नागपुर म्यूनिसिपल अधिकारियों ने फहीम खान नामक व्यक्ति के घर के कुछ हिस्सों को बुलडोजर से ढहा दिया। यह व्यक्ति 17 मार्च को शहर में हुये दंगों का आरोपी है। इस घटना के कुछ घंटे बाद, बम्बई उच्च न्यायालय ने मकान गिराये जाने पर स्टे दे दिया तथा उस क्षेत्र के अन्य मकानों को ध्वस्त करने प्रक्रिया रोकने के आदेश जारी कर दिये। इससे

उत्तर प्रदेश के मु.मंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘बुलडोजर जस्टिस’ के पक्ष में कहा, ‘कुछ लोगों के लिए जरूरी होता है, उनको उसी भाषा में बताया जाए, जो वे समझते हैं।’

पहले 23 फरवरी को, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक मकान ढहा दिया गया था। इस घटना को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान ‘भारत-विरोधी नारे’ लगाये जाने के दण्ड के रूप में देखा गया था। किताबुल्ला-हमीदुल्ला ने सर्वोच्च न्यायालय पहुँच कर, अदालत के 13 नवम्बर के आदेश की मानहानि का आरोप लगाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में सोमवार को नोटिस जारी करके, सम्बंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

‘हयूमन राइट्स ग्रुप एनिवर्सिटी इंटरनेशनल’ के अनुसार, आप-शासित पंजाब के अलावा, चार भाजपा-शासित राज्यों में, सर्वोच्च न्यायालय

के 13 नवम्बर के आदेश के बाद, 128 भवन ध्वस्त किये जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश में अपराधों के आरोपियों के घरों को मनमर्जी से गिरा देना निषिद्ध करार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन बिल्कुल स्पष्ट है: ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से पहले, सम्बंधित व्यक्ति को मकान गिराये जाने की तारीख से 15 दिन पहले ‘कारण बताओ’ नोटिस दिया जायेगा, तथा इसके बाद प्रभावित पक्ष को अपील के लिये 15 दिन का समय और दिया जायेगा। अदालत के लिये उसी तारीख की जाचिका अर्पित करनी होगी।

कमिश्नर के समक्ष पेश की जायेगी तथा उसे सार्वजनिक किया जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये गाइडलाइन सडक, फुटपाथ या जल-भंडारण तंत्रों, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर नहीं अनधिकृत मकानों के मामले में लागू नहीं होगी। अदालत द्वारा आदेशित ध्वस्तीकरण के मामलों में भी ये गाइडलाइन लागू नहीं होंगी। लेकिन जैसा इस मामले में हुआ है, राज्य सरकारें बुलडोजर कार्यवाही करने में इन्हीं छूटों का सहारा ले रही हैं। ध्वस्तीकरण निषेध की सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन्स को लेकर राजनेताओं का चिन्तित होना अनावश्यक प्रतीत नहीं हो रहा है। ‘बुलडोजर कार्यवाही’ के बचाव में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि ‘कुछ लोगों से निबटने के लिये उसी तरीके की जरूरत होती है, जिसे वे समझते हैं।..... (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान हाई कोर्ट में चार नए जज नियुक्त

जयपुर, 26 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट को चार नए न्यायाधीश मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलॉजियम की ओर से गत दिनों आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह के नामों की भेजी सिफारिश को केन्द्र सरकार ने मान लिया है। वहीं, राष्ट्रपति भवन से इनके नियुक्ति वारंट भी जारी

सुप्रीम कोर्ट कोलॉजियम ने चार जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसे केन्द्र सरकार ने मान लिया है।

उन देशों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो पारंपरिक रूप से इस बात के लिए जाने जाते हैं कि सरकार का खर्च सीमा में हो और ऋणभार ज्यादा बढ़े। ओ.ई.सी.डी., जिसे समृद्ध देशों का क्लब कहा जाता है, ने यह खुलासा किया है कि यूरोप के अत्यधिक विकसित देश अपने बकाया कर्जों का भुगतान करने के लिए अपने वार्षिक रक्षा

## सदा से वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर देशों की इस मुद्दे पर हालत काफी चिंताजनक है

ये तथाकथित अमीर देश, अपने ऋणों पर जो ब्याज दे रहे हैं, वो उनके रक्षा बजट से भी ज्यादा हैं

-अंजन राय-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (ओ.ई.सी.डी.) ने 2025 के लिए अपनी वैश्विक कर्ज सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जो विकास और आय के स्पेक्ट्रम में देशों की कुल कर्ज की स्थिति को लेकर एक गंभीर तस्वीर पेश करती है।

इसमें कई सच्चाइयों सामने आई हैं, जिनमें उन देशों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो पारंपरिक रूप से इस बात के लिए जाने जाते हैं कि सरकार का खर्च सीमा में हो और ऋणभार ज्यादा बढ़े।

ओ.ई.सी.डी., जिसे समृद्ध देशों का क्लब कहा जाता है, ने यह खुलासा किया है कि यूरोप के अत्यधिक विकसित देश अपने बकाया कर्जों का भुगतान करने के लिए अपने वार्षिक रक्षा

यह भी एक कारण है कि वे रूस के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि, जैसा कि ट्रंप की शिकायत है, इन देशों की आदत पड़ गई है कि उनकी सुरक्षा का आर्थिक भार तो अमेरिका वहन कर ही लेगा। अतः, उनकी सेना की स्थिति काफी कमजोर है, रूस की तुलना में।

ये सभी तथ्य, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (ओ.ई.सी.डी.) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में लिखे हैं।

उन्नत देशों का अन्तरराष्ट्रीय ऋण 17 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, 2025 में, जबकि 2023 में यह ऋण 14 ट्रिलियन डॉलर ही था। दूसरी ओर विकासशील देशों का ऋण 2024 में कुल तीन ट्रिलियन डॉलर ही था।

पर, यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार के ऋण कभी अदा नहीं होते तथा पुराने ऋण की सर्विस के लिये नये ऋण ले लिये जाते हैं, कुछ और बढ़ी हुई ब्याज दर पर।

और, इस प्रकार ऋण पर ब्याज का भार बढ़ता ही रहता है। परन्तु, भारत के ऋण की स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, अब तक।

बजट से अधिक खर्चा कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह उस बात को रेखांकित करता है, जो

अमेरिकियों ने बहुत कठोर शब्दों में उनसे कही थी कि ये देश खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त

से उन्हें बचाए। इस आर्थिक संकेतक से ही यह बात समझ में आती है कि जब आक्रामक रूस उनके दरवाजे पर पहुँच गया है और अमेरिका ने उनके रक्षा बिलों का भुगतान करने से इन्कार कर दिया है, तो यूरोपीय देश कितना असहय महसूस कर रहे हैं।

फिर भी दूसरों को उपदेश देने की आदत आसानी से नहीं जाती। ओ.ई.सी.डी. रिपोर्ट ने विकसित देशों के साथ-साथ तथाकथित उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकसित देशों की कर्ज प्रोफाइल का भी विश्लेषण किया है। महामारी के बाद, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए दिए गए कृत्रिम प्रोत्साहनों के कारण विकसित देशों के कर्ज से जी.डी.पी. अनुपात बहुत ऊँचे स्तर पर पहुँच गया है। वैसे, जब हम उभरती अर्थव्यवस्थाओं और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा को जान से मारने की धमकी

जयपुर, 26 मार्च। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा को बुधवार देर शाम को जयपुर सेंट्रल जेल से जान से मारने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी में सामने आया है कि एक बदमाश ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर बैरवा

पता चला है कि जयपुर सेंट्रल जेल से किसी बदमाश ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर धमकी दी।

को मारने की धमकी दी है। इसके बाद, जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम तैनात ड्यूटी ऑफिसर ने धमकी भरा फोन आने की सूचना पुलिस के आलाधिकारी को दी। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम इंचार्ज से जिस नंबर से फोन आया, उस मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की गई। मोबाइल की लोकेशन जयपुर सेंट्रल जेल आई। पूर्व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)